THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) to (f) The response of the private sector to the private power programme of Government of India has been encouraging with 128 expressions of interest for setting up power projects in the private sectors. These include 56 proposals from foreign investors, details of which are given in Anne-xure *[See Appendix. 180, Annexure No. 34].* The power policy is amended from time to time, keeping in view the changing requirements.

Electricity Regulatory Commissions in the Centre and States

1400. SHRI NILOTPAL BASU:
SHRI MD. SALIM:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is a proposal under the Common Minimum National Action Plan for power to set up State level independent State Electricity Regulatory Commissions (SERC);

(b) if so, whether Government proposed to set up an independent Central Electricity Reguletory Commission (CERC) also; if not the reasons therefor;

(c) whether appeals against orders of SERC will lie before the respective State High Courts or before the proposed CERC; and

(d) whether appeals against orders of CERC will lie before the Supreme Court; if not the reasons therefor and the methodology proposed to resolve disputes between central utilities and the state agencies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) Yes. Sir.

(b) to (d) The proposals in this regard are under consideration of Government.

नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम (एन. जे. पी. सी.) के अधिकारी

1401. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 नवम्बर, 1995 से 31 दिसम्बर, 1996 तक नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम के कौन-कौन से अधिकारी कितने-कितने दिनों तक दिल्ली और शिमला स्थित कार्यालयों में रहे तथा उन्होंने कितना-कितना यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता लिया,

(ख) दिल्ली के भाई बीर सिंह मार्ग स्थित नाथपा-झाकड़ी विद्युत निगम की कार्यालय में काम कर रहे 36 व्यक्ति किन-किन पदों पर है और शिमला स्थित कार्यालय में कितने अधिकारी किन-किन पदों पर काम कर रहे हैं,

(ग) क्या नाथपा-झाकड़ी विद्युत निगम के दोनों कार्यालयों द्वारा प्रतिमाह अलग अलग कितना-कितना किराया दिया जा रहा है, और

(घ) क्या नाथपा-झाकड़ी विद्युत निगम के दिल्ली स्थित कार्यालय की 7727 वर्ग फुट भूमि वापस करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसमें कितना समय लगेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुनोपालाचारी) : (क) 1.11.95 से 31.12.96 के दौरान दिल्ली में नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम (एन.जेपीसी) के अधिकारियों द्वारा बिताए गए दिनों की संख्या को विवरण में दर्शाया गया है (नीचे देखिए) । इसी अवधि के दौरान दिल्ली में उनके रहने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के भुगतान हेतु एनजेपीसी द्वारा लगभग भत्ते/दैनिक भत्ते के भुगतान हेतु एनजेपीसी द्वारा लगभग 4.21 लाख रूपए का व्यय किया गया ।

(ख) दिल्ली और शिमला में तैनात कार्यपालकों, पर्यवेक्षकों और अन्य कर्मचारियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है,

क्र. सं.	कर्मचारियों की श्रेणी	तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	
		दिल्ली	शिमला
1.	कार्यपालक	13	124
2.	पर्यवेक्षक	1	32
3.	अन्य कर्मचारी	22	232
	जोड़	36	388

(ग) नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम नई दिल्ली और शिमला में किराए पर लिए गए कार्यालयों हेतु क्रमशः 3,55,448/- रूपए तथा 2,27,672/- रूपए मासिक किराए का भुगतान कर रहा है।

(घ) नाथपा –झाकड़ी विद्युत निगम द्वारा अपने दिल्ली में किराए पर लिए गए 7727 वर्ग फुट कार्यालय को भूमि 1 अप्रैल, 1997 तक वापिस करने हेतु पहले हो कदम उठाए जा रहे हैं।

विवरण

1.11.95 से 31.12.96 के दौरान एनजेपीसी के अधिकारियों द्वारा दिल्ली में बिताए गए दिनों की संख्या को दर्शनें वाला विवरण

क्र. सं.	नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम के अधिकारियों का ब्यौरा	1.11.95 से 31.12.96 के दौरान दिल्ली में बिताए गए दिनों की सं0
1.	अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक	243
2.	निदेशक (कार्मिक)	180
3.	निदेशक (सिविल)	195
4.	निदेशक (विद्युत)	187
5.	निदेशक (वित्त)	20
6.	कार्यकारी निदेशक (सतर्कता)	216
7.	उप-प्रबंधक (कार्मिक)	46
8.	सहायक कार्यकारी अभियंता (मुख्यालय आयोजना)	4
9.	वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक)	103
10.	प्रबंधक (कार्मिक)	80
11.	प्रबंधक (जनसम्पर्क)	170
12.	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी	4
13.	उप-प्रबंधक (राजभाषा)	92
14.	कार्मिक अधिकारी	95
15.	अधिकारी (बागवानी)	19
16.	सहायक अधिकारी (प्रशिक्षण)	59
17.	सहायक अभियंता (ई.डी.पी.)	10

क्र. सं.	नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम के अधिकारियों का ब्यौरा	1.11.95 से 31.12.96 के दौरान दिल्ली में बिताए गए दिनों की सं0
18.	सहायक अभियंता (सिविल)	133
19.	उप-प्रबंधक (कार्मिक)	380
20.	प्रबंधक (कार्मिक)	140

*अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक, एनजेपीसी को 30.1.96 से 31.10.96 तक अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद के वर्तमान कर्तव्य-भार भी सौपें गए थे।

Private Sector' Participation in Power Generation

1402. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have received offers from private sector to participate in power generation in the country;

(b) if so, the names of such companies, both Indian and Foreign, which have made the offers, as on 15th February, 1997;

(c) the details of offers made and the action taken by Government thereon;

(d) whether those offers are adequate to meet the needs of the country;

(c) whether Government propose to take steps to remove constraints faced by private investors; and

(f) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) to (c) 128 proposals have been received from private promoters for setting up generation capacity of 70.549 MW and involving a projected investment of Rs. 2.53, 405.29 crores. These include 96 proposals on the Memorandum of Understanding (MoU)/ Letter of Intent (Lol), etc. route costing above Rs. 100 crores and 36 proposals on the competitive bidding route costing above Rs. 1000 crores. Details are given in Anncxure. Of the proposals on the MoU/LoI. etc. route listed in the Annexure. *[See* Appendix 180, Annexure No. 35] Central Electricity authority (CEA) has accorded techno-economic clearance to 20 proposals and has accorded 'in-principle' clearance to 76 proposals. Government of India is closely monitoring progress of all the private power projects awarded through the MoU/LoI. etc. route with projected costs exceeding Rs. 100 crores and has also fixed March 31, 1997 as the last date for filing their Detailed Project Reports with CEA for its techno-economic clearance.

(d) It has been assessed that in the Ninth Plan, a need based capacity addition of around 57,000 MW would need to be added to meet the demand for power during the Plan. In the event of their fructifying, the offers received for setting up power projects in the private sector arc adequate to meet this requirement of the country.

(e) and (f) Government have been monitoring the progress of the private sector power projects from time to time and providing necessary assistance for them to obtain necessary inputs/clearances. Government have also constituted a High Powered Board which also monitors the progress of the private sector power projects and expedite the clearances.